आय–व्ययक वित्तीय 2016–17

प्रमुख बिन्दु

1–आय

- वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियों में रु0 32275.87 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है।
- वर्ष 2016–17 में आय–व्ययक अनुमान में कर राजस्व रु0 18131.13 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है,
- करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रु0 2793.43 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल प्राप्तियॉ रु 039912.00 करोड़ अनुमानित है।

2–व्यय

- वर्ष 2016–17 में कुल रू0 40422.20 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
- वर्ष 2016–17 में कुल व्यय में रु0 32250.39 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय तथा रु0 8171.81 करोड़ पूॅजी लेखे का व्यय अनुमानित है।
- इस वित्तीय वर्ष में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों पर लगभग रु011015.62 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है।
- आयोजनागत मद में लगभग रु0 15931.60 करोड़ व्यय अनुमानित है।

3– राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है।
- राजकोषीय घाटा रु0 6072.97 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।
- राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा के सम्बन्ध में आय–व्ययक 2016–17 के परिणाम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ0आर0बी0एम0) अधिनिमय के लक्ष्यों (राजस्व घाटा शून्य , राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 का 3 प्रतिशत) की सीमान्तर्गत है।

4– अन्य प्रमुख बिन्दु

- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ''मेरा गाँव मेरी सड़क'' नाम की नई योजना प्रारम्भ की गई है।
- पारंपरिक अवधारणाओं, मान्यताओं तथा विश्वास से जन सामान्य को जोड़े रखने के लिये राज्य सरकार ने ''हिटो पहाड़, हिटो गाँव'' की अवधारणा के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।
- तेजी से हो रहे पलायन को रोकने तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नेपा, खुरपिया, पराग, सितारगंज में ''मेक इन इण्डिया'' के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना की जायेगी।
- गरीब, गॉव, गुरूजी, गन्ना– गुड़, गाय– गौशाला–गौचर, गंगा, गाड–गधेरा, गुजर–बसर, गहत–गलगल, गर्दैणी, गेठी और गदुवा–गडेरी के चारों तरफ विकास की सम्भावनाएँ।

- मडुवा, रामदाना एवं उगल/फाफर के उत्पादन पर प्रोत्साहन धनराशि की योजना गतिमान है तथा सरकार जैविक गुड़ उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।
- प्रदेश में कॉपरेटिव फार्मिग को प्रोत्साहित करने हेतु 'माधो सिंह भण्ड़ारी कृषि सहभागिता योजना'' प्रस्तावित है।
- प्रदेश में प्रथम बार सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है।
- सीमान्त व पर्वतीय खेती के उन्नयन हेतु एक कार्य योजना बनाने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप गठित किया जायेगा तथा माधो सिंह भण्ड़ारी कृषि सहभागिता योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- जड़ी–बूटी की खेती को प्रोत्साहित किये जाने हेतु इस वर्ष 20 गांवों में जड़ी–बूटियां रोपित की जाएंगी।
- प्रथम बार माल्टा एंव पहाड़ी नीबू का समर्थन मूल्य निश्चित करते हुए उपार्जन किया गया है।
- सरकार बगास से चलने वाले पॉवर प्लान्ट, एफल्यूएंट ट्रीटमैन्ट प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
- किशोरी बालिका हेतु सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- हल्द्वानी में एक अन्तर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी की स्थापना की जायेगी।
- गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों विशेषतः गैरसैंण पहुंच वाली सड़कों, विद्युत व पेयजल उपलब्धता हेतु सम्बन्धित विभागों के लिए आवश्यक बजटीय व्यवस्था की गयी है।
- नयी प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- वरूणावत पर्वत के अन्तर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेन्ट कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- अल्मोड़ा आवासीय विश्व विधालय की स्थापना, मॉडल स्कूलों की स्थापना तथता रमसा के अन्तर्गत ''उन्नति योजना'' हेतु धनराशि प्राविधानित की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवंर्धन योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना तथा पारितोषिक योजना प्रारम्भ की जा रही हैं।
- प्रदेश के विभिन्न स्थानों को योग सर्किट के रूप में विकसित कर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, साथ ही एक हजार व्यक्तियों को पार्ट टाईम योग प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड मैट्रो, नगरीय अस्थापना एवं भवन कॉरपोरेशन को सीड मनी हेतु एक मुश्त धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- गोरखा कल्याण परिषद की योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- समाज के अति पिछड़ें वर्गो हेतु ''बाबा साहेब फूले योजना'' प्रारम्भ की जा रही है।
- राजभर समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु ''राजा सुहेल देव'' छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है।
- पिछड़े वर्ग की प्रतिभावान छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए राजा विजय सिंह पारितोषिक योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- सगुन अक्षर गाने वाली महिलाओं व दाई मां को भी पेंशन योजना के तहत लाया जायेगा तथा भीख मांगने वाले बच्चों को आई0सी0पी0एस0 योजनान्तर्गत संचालित सवेरा योजना के तहत लाया जायेगा।
- जागर महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी तथा जगरियों/ डंगरियों को भी पेंशन योजनान्तर्गत लाया जायेगा।
- प्रमुख यात्रा मार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों में प्रमुख बिन्दुओं पर स्थानीय क्राफ्ट एवं फूड सराय विकसित की जायेगी। इन्हीं सरायों में 50 प्रतिशत दुकानें–स्टॉल स्थानीय युवाओं व महिलाओं को आवंटित की जायेंगी।
- सिविल सर्विसेज व उच्च पदों के लिए प्रयास कर रही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी तथा राज्य महिला नीति घोषित की जायेगी।
- अर्द्ध सैनिक बल निदेशालय के गठन हेतु विभिन्न मदों में धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास रोजगार के अवसर आदि के लिए उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद का गठन तथा मुस्लिम छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- नैनीसार (अल्मोड़ा) में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी श्रमिकों के बच्चों के प्रशिक्षण के लिए आवासीय आई0टी0आई0 खोला जायेगा।
- राज्य के मेडिकल कालेजों व निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों तथा बेस हास्पिटल में एक–एक स्पेशलाईज वार्ड भवन एवं अन्य कर्मी श्रमिकों के लिए निर्मित किये जाएंगे। इस हेतु धन की व्यवस्था सैस से की जायेगी।
- उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य कल्याण निगम हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- उच्च प्रशिक्षण देकर 2000 क्राफ्टस वुमन व क्राफ्टस मैन तैयार किये जाएंगे।
- उत्तराखण्डी भवन शैली व व्यंजनों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने हेतु कार्य दल गठित किये जा रहे हैं।
- स्टार्टप एण्ड स्टैण्डप उद्यमिता विकास हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- सिडकुल में 200 एकड़ भूमि में महिला उद्यमी इंडस्ट्रीयल पार्क स्थापित किया जायेगा।
- इंदिरा दुग्ध विकास मंडल स्थापित किये जाएंगे।

- आशा, आंगनवाड़ी से सम्बद्ध बहनों महिला समाख्याओं, भोजन माताओं को विशेष बोनस राशि दी जायेगी। सम्बन्धित विभाग इस राशि की व्यवस्था करेंगे।
- जयानन्द भारती दस्तकार प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की दशा में रेशा खरीद हेतु अनुदान के लिये धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- काशीपुर में नेपा लिमिटेड भूमि के हस्तानान्तरण हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- काशीपुर में फूड पार्क की स्थापना तथा लघु उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट को कानूनी जामा पहनाया जायेगा।
- मुख्यमंत्री व्यावसायिक चालक बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- सामाजिक सुधार व पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए कार्य करने वालों को प्रतिवर्ष वीरांगना अवन्ती बाई लोधी समाज रत्न पुरस्कार से राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जायेगा।
- स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले उत्तराखण्ड में जन्मे ऐसे महापुरूष जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग से थे, उनकी स्मृति में राज्य के प्रमुख संस्थानों का नामकरण किया जायेगा और उन संस्थानों में उनकी मूर्ति स्थापित की जायेगी।
- 10 ओल्ड एज वेलनेस पार्क विकसित किये जाएंगे। वृद्ध जनों को डायलेसीस हेतु मुख्यमंत्री कोष से पच्चीस हजार तक वार्षिक अनुदान दिया जायेगा।
- दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में भर्ती व स्वरोजगार, चिकित्सा सुविधा विस्तार हेतु एक माह में दिव्यांग रोजगार नीति एवं कल्याण निधि स्थापित की जायेगी।
- ग्राम सभाओं और व्यक्तियों को वर्षा जल संग्रह के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार एक माह के अन्दर वाटर बोनस नीति घोषित करेगी।
- राज्य सरकार समाज सुधारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री खुशीराम आर्य के नाम को समर्पित 50 खुशी ग्राम व बाखलियों को स्थापित करेगी। इस अभिप्राय से जिलाधिकारियों को भूमि आवंटन के अधिकार दिये जा रहे हैं।
- महिला दिव्यांगों को विशेष सहायता स्वरूप पच्चीस हजार, बीस हजार व पन्द्रह हजार एक समय की विशेष सहायता प्रतिवर्ष दी जायेगी।
- सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं चाहें वे आउट सोर्सिंग से कार्यरत हों, को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जायेगा।
- राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना तथा डेयरी परियोजनाओं के तहत पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई–पशुधन हाट, राष्ट्रीय–देशीय नस्ल जेनोमिक केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया है।

- राज्य में मसाला मिर्च के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान योजना तथा वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- रवाई घाटी में उद्यान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा मिशन एप्पल योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- गंगोलीहाट, घनसाली, बागेश्वर, सितारगंज, बाजपुर, भगवानपुर, लक्सर, झबरेड़ा, अल्मोड़ा, खटीमा, कालेश्वर, चम्पावत, श्रीनगर, पिथौरागढ, लोहाघाट, ताड़ीखेत एवं पुरोला में बस अड्डों/ बस डिपों का निर्माण किया जायेगा।
- थारू एवं बोक्सा जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना, राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना, मेरा गांव मेरी सड़क योजना एवं इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना आदि राज्य में सफलता पूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं।
- राज्य सरकार द्वारा डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना तथा प्रधानों व पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायतों को सुनने के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाया जायेगा।
- मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन जीवों से खेती की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जंगली जानवरों/ सुअर रोधी दीवार के निर्माण कार्य जारी हैं।
- समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो हेतु डा0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा अति पिछड़े वर्ग हेतु बाबा साहेब फूले योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- केदारनाथ में आयी दैवीय आपदा में विधवा हुई महिलाओं को भरण पोषण हेतु अच्छी नस्ल की एक गाय उपलब्ध कराये जाने की नयी योजना स्वीकृत की गयी है।
- पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में एक भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।